



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

१०/८
२५/६/९८

सं 129]
No. 129]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 20, 1998 / चैत्र 30, 1920
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 20, 1998/CHAITRA 30, 1920

पर्यावरण और बन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1998

सांकेतिक 190 (अ) — केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 22) की धारा 22 की उपधारा (1) के खंड (ख) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बेतन, भर्ते और सेवा की शर्तें) नियम, 1998 है।

(2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ :— इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 22) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "उपाध्यक्ष" से प्राधिकरण का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।

3. पदावधि :— अध्यक्ष उस तारीख से जिसको वह अपना पदग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, किन्तु वह तीन वर्ष की दूसरी अवधि के लिए युनियनिक का पात्र होगा :

परन्तु यह कि कोई अध्यक्ष सत्र वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् इसमें जो भी पूर्वतर हो, इस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

4. अध्यक्ष का बेतन :— अध्यक्ष, भारत सरकार के सचिव के बेतनमान का हकदार होगा जो 26,000 रु. (नियत) है। बेतन विद्यमान आदेशों के अनुसार नियत किया जाएगा जो बेतन में से पेंशन को घटा कर होगा।

(1) अध्यक्ष, उस दर से महगाई भसे और नगरपूर्ति भते का हकदार होगा जो भारत सरकार के सचिव को अनुज्ञेय है।

(2) अध्यक्ष को छुट्टी यात्रा रियायत (एल०टी०सी०), के दौरे पर यात्रा भता और दैनिक भता का संदाय उस अनुसार किया जाएगा जो भारत सरकार के सचिव को लागू हो। वह केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाए जाने वाले अतिथि गृह/निरीक्षण बंगला में अस्थाई सरकारी वास की सुविधा का बहिस्थान

पर सामान्य किराए के संदाय पर, जहां लागू हो, उस श्रेणी के लिए भी हकदार होगा, जिसका भारत सरकार सचिव पात्र है।

(3) अध्यक्ष द्वारा विदेश में सरकारी निरीक्षण ऐसे सरकारी आदेशों के अनुसार ही किया जाएगा जो भारत सरकार में समान श्रेणी के अधिकारियों को लागू हों। घरेलू दौरों के लिए अध्यक्ष प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव को सूचित करेगा।

(4) अध्यक्ष केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा स्कीम में उपबंधित उन चिकित्सीय उपचार और अस्पताल सुविधाओं का हकदार होगा जो किसी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को लागू हैं। उन स्थानों पर जहां केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा स्कीम प्रवर्तन में नहीं है वहां वह केन्द्रीय सेवा (चिकित्सीय परिचयों) नियमों में उपबंधित प्रतिपूर्ति सुविधाओं का हकदार होगा।

5. छुट्टी :—अध्यक्ष सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 30 दिन की उपार्जित छुट्टी का हकदार होगा। छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन संदाय केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा शासित होगा। कोई व्यक्ति किसी भी समय उसके खाते में जमा उपार्जित छुट्टी के पचास प्रतिशत के नकदीकरण का हकदार होगा।

6. साधारण भविष्य निधि/अधिदायी भविष्य निधि, पेंशन और उपदान :—अध्यक्ष, अधिदायी भविष्य निधि नियमों द्वारा शासित होगा और साधारण भविष्य निधि के नियमों के अधीन अधिदाय करने का कोई विकल्प नहीं होगा। प्राधिकरण में की गई सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन और उपदान अनुज्ञय नहीं होगा।

7. पुनर्नियोजन के लिए पात्रता :—ऐसे संगठनों की बाबत जो राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण के कामकाज संबंधी अधिकारिता के भीतर आते हैं, अध्यक्ष का पद छोड़ने के पश्चात् दो वर्ष के लिए अध्यक्ष का प्राइवेट नियोजन वर्जित होगा।

8. परिवहन :—अध्यक्ष निवास और कार्यालय के बीच परिवहन के लिए उसकी निजी कार के प्रयोग और अनुरक्षण के लिए तीन हजार रुपया और पांच हजार रुपया प्रतिमाह के बीच ऐसी प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा जो समय-समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (छोटोंपीठी) द्वारा नियत की जाए इसके अंतर्गत ड्राइवर का वेतन भी होगा जो सरकारी सेवक नहीं होगा।

9. वास सुविधा :—अध्यक्ष, यदि वह दिल्ली में रुकता है तो उसके द्वारा लिए गए आधारिक वेतन के तीस प्रतिशत की दर से मकान किराए भते का हकदार है। दिल्ली से बाहर वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगभग 350 वर्गमीटर माप के निर्मित क्षेत्र की भाड़े पर ली गई ऐसी असंज्ञित वास सुविधा का, जो संबंधित नगर निकायों के विनियम के अधीन अनुज्ञय संलग्न समुचित खुली भूमि क्षेत्र के साथ होगी, हकदार होगा।

10. वर्तमान अध्यक्ष से संबंधित विशेष उपबंधि :—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व नियुक्त और पद धारण कर रहा अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायलय के पीठासीन न्यायाधीश के समकक्ष होगा :—

परन्तु यह कि वेतन उच्चतम न्यायलय के पीठासीन न्यायाधीश के वेतन में उसके मामले में नियत पेंशन (संराशिकरण से पूर्व) घटा कर होगा।

11. उपाध्यक्ष की पदाब्धि :—उपाध्यक्ष उस तारीख से जिसको वह अपना पदग्रहण करता है तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा किन्तु वह तीन वर्ष की दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

परन्तु यह कि कोई उपाध्यक्ष पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् इसमें जो भी पूर्वतर हो, इस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

12. उपाध्यक्ष का वेतन :—उपाध्यक्ष, भारत सरकार के सचिव के वेतनभान का हकदार होगी/होगा जो 26,000 रु० (नियत) है। वेतन विधमान आदेशों के अनुसार नियत किया जाएगा; जो वेतन में से पेंशन को घटा कर होगा।

(1) उपाध्यक्ष, उस दर से घंटगाई भते और नगरप्रतिपूर्ति भते का हकदार होगा जो भारत सरकार के सचिव को अनुज्ञय है।

(2) उपाध्यक्ष को छुट्टी यात्रा रियायत (एल०टी०सी०), के दौरे पर यात्रा भता और दैनिक भता का संदाय उस अनुसार किया जाएगा; जो भारत सरकार के सचिव को लागू हो। वह केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाए जाने वाले अतिथि गृह/निरीक्षण बंगला में अस्थाई सरकारी वास की सुविधा का बहिस्थान पर सामान्य किराए के संदाय पर, जहां लागू हो, उस श्रेणी के लिए भी हकदार होगा, जिसका भारत सरकार सचिव पात्र है।

(3) उपाध्यक्ष द्वारा विदेश में सरकारी निरीक्षण भारत सरकार के सचिवों को लागू सरकारी आदेशों द्वारा शासित होगा।

(4) उपाध्यक्ष केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा स्कीम में उपबंधित उन चिकित्सीय उपचार और अस्पताल सुविधाओं का हकदार होगा; जो किसी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को लागू हैं। उन स्थानों पर जहां केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा स्कीम प्रवर्तन में नहीं है वहां वह केन्द्रीय सेवा (चिकित्सीय परिचयों) नियमों में उपबंधित प्रतिपूर्ति सेवाओं का हकदार होगा।

13. छुट्टी :—उपाध्यक्ष सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 30 दिन की उपार्जित छुट्टी का हकदार होगा। छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन संदाय केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा शासित होगा। कोई व्यक्ति किसी भी समय उसके खाते में जमा उपार्जित छुट्टी के पचास प्रतिशत के नकदीकरण का हकदार होगा।

14. उपाध्यक्ष की छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारी :—

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

15. साधारण भविष्य निधि/अभिदायी भविष्य निधि, पेंशन और उपदान :—उपाध्यक्ष, अभिदायी भविष्य निधि नियमों द्वारा शासित होगा और साधारण भविष्य निधि के नियमों के अधीन अभिदाय करने का कोई विकल्प नहीं होगा। प्राधिकरण में की गई सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन और उपदान अनुज्ञय नहीं होगा।

16. पुनर्नियोजन के लिए पात्रता :—ऐसे संगठनों की बाबत जो राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण के काम-काज संबंधी अधिकारिता के भीतर आते हैं, उपाध्यक्ष के पद छोड़ने के पश्चात् दो वर्ष के लिए उपाध्यक्ष का प्राइवेट नियोजन वर्जित होगा।

17. परिवहन :—उपाध्यक्ष, निवास और कार्यालय के बीच परिवहन के लिए उसकी निजी कार के प्रयोग और अनुरक्षण के लिए 3000 रु. और 5000 रु. प्रतिमाह के बीच ऐसी प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा, जो समय-समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण निभाग (डी.ओ.पी.टी.) द्वारा नियत की जाए। इसके अंतर्गत ड्राइवर का वेतन भी होगा जो सरकारी सेवक नहीं होगा।

18. बास-सुविधा :—उपाध्यक्ष, यदि वह दिल्ली में रुकता है तो उसके द्वारा लिए गए आधारिक वेतन के तीस प्रतिशत की दर से मकान किराए भरते का हकदार है। दिल्ली से बाहर वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगभग 300 बर्गमीटर माप के निर्भित क्षेत्र की भाड़े पर ली गई ऐसी असज्जित बास-सुविधा का, जो संबंधित नगर निकायों के अधीन अनुज्ञय संलग्न समुचित खुली भूमिक्षेत्र के साथ होगी, हकदार होगा।

19. प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध :—जहाँ कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई सेवानिवृत्त सरकारी सेवक है या अन्य संस्था या स्वायत्त निकाय का सेवानिवृत्त सेवक है और किसी पूर्ववर्ती सेवा की बाबत कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है, उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है तो इन नियमों के अधीन उसे अनुज्ञय वेतन में से उस पेंशन की रकम को और यदि पेंशन के भाग के बदले कुछ प्राप्त किया था तो पेंशन के उस भाग की रकम में से उसका संराशित मूल्य, घटा दिया जाएगा।

20. व्याख्या :—कोई ऐसा विषय, जिसका उपबंध इन नियमों में अधिव्यक्ति रूप से नहीं किया गया है, प्रत्येक मामले में, केन्द्रीय सरकार को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

[फा. सं. क्यू.-14011/1/97-सीपीडब्लू]

विजय शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 1998

G.S.R. 190 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (b) of sub-section (2) of section 22 of the National Environment Appellate Authority Act, 1997 (No. 22 of 1997), the Central Government hereby makes the following rules, namely :

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the National Environment Appellate Authority (Salary, Allowances and Conditions of Service of Chairperson and Vice-Chairperson) Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the National Environment Appellate Authority Act, 1997 (22 of 1997);

(b) "Authority" means the National Environment Appellate Authority established under sub-section (1) of section 3 of the Act;

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Authority;

(d) "Vice-Chairperson" means the Vice-Chairperson of the Authority;

3. Tenure :

A Chairperson shall hold office for a period of three years from the date on which he enters his office but shall be eligible for re-appointment for another term of three years : provided that no Chairperson shall hold office as such after he attains the age of seventy years, whichever is earlier.

4. Pay of Chairperson :

A Chairperson shall be entitled to the pay scale of Secretary to the Government of India, i.e. Rs. 26,000/- (fixed). The pay shall be fixed in accordance with prevailing orders i.e. pay minus pension.

- (i) The Chairperson shall be entitled to dearness allowance and city compensatory allowance at the rates admissible to a Secretary to the Government of India.
- (ii) Leave Travel Concession (LTC), Travelling Allowance and Daily Allowance on tour, shall be paid to the Chairperson as applicable to a Secretary to the Government of India. He will also be entitled to facility of temporary Government accommodation in guest house/inspection bungalow run by the Central Government, wherever applicable, on payment of normal rent at outstation, of the class to which a Secretary to the Government of India is eligible.
- (iii) Official visits abroad by a Chairperson shall be undertaken only in accordance with Government orders as applicable to officers of equal grade in the Government of India. For domestic tours, the Chairperson would keep the Secretary of the administrative Ministry/Department informed.
- (iv) A Chairperson shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as provided in the Central Government Health Scheme (CGHS) as applicable to a retired Government Servant. At places where the CGHS scheme is not in operation, he shall be entitled to reimbursement facilities provided under the Central Services (Medical Attendance) Rules.

5. Leave :

A Chairperson would be entitled to 30 days of Earned leave, for every year of service. The payment of leave salary during leave shall be governed by rule 40 of Central Civil Services (Leave) Rules, 1972. A person would be entitled to encashment of 50% of earned leave to his credit at any time.

6. GPF/CPF, Pension and Gratuity :

A Chairperson would be governed by Contributory Provident Fund Rules and no option to subscribe under General Provident Fund Rules will be available. Additional pension and gratuity will not be admissible for service rendered in the Authority.

7. Eligibility for Re-employment:

There shall be bar on private employment of Chairperson for two years in respect of organisations that fall within the operational jurisdiction of the National Environment appellate authority, after demitting office of Chairperson.

8. Transport :

A Chairperson is eligible for reimbursement between Rs. 3000/- and Rs. 5000/- per month as fixed by the Department of Personnel and Training, from time to time, for the use and maintenance of his personal car for transportation between residence and office. This would include the salary of a driver who would not be a Government servant.

9. Accommodation :

A Chairperson is entitled for House Rent Allowance at the rate of 30% of the basic pay drawn, if he stays in Delhi. Outside Delhi, he shall be entitled to rented unfurnished accommodation with built up area measuring around 350 sq. meters in the National Capital Region (NCR) with suitable open land area appurtenant as permissible under the regulations of the concerned municipal bodies.

10. Special Provisions relating to existing Chairperson :

Notwithstanding anything contained in these rules, salary, allowances and conditions of service of the Chairperson appointed before and holding office on, the commencement of these rules shall be, at par with a sitting Judge of the Supreme Court of India;

Provided that the salary being pay of a sitting judge of the Supreme Court minus pension (before commutation) fixed in his case.

11. Tenure of Vice-Chairperson:

A Vice-Chairperson shall hold office for a period of three years from the date on which he/she enters upon his/her office but shall be eligible for re-appointment for another term of three years :

Provided that no Vice-Chairperson shall hold office as such after he/she has attained the age of sixty five years, whichever is earlier.

12. Pay of Vice-Chairperson :

A Vice-Chairperson shall be entitled to the pay scale of Secretary to the Government of India, i.e., Rs. 26,000 (fixed). The pay shall be fixed in accordance with prevailing orders i.e. pay minus pension.

- (i) The Vice-Chairperson shall be entitled to dearness allowance and city compensatory allowance at the rates admissible to a Secretary to the Government of India.
- (ii) Leave Travel Concession (LTC), Travelling Allowance and Daily Allowance on tour, shall be paid to the Chairperson as applicable to a Secretary to the Government of India. He/She will also be entitled to facility of temporary Government accommodation in guest house/inspection bungalow run by the Central Government, wherever applicable, on payment of normal rent at outstation, of the class to which a Secretary to the Government of India is eligible.
- (iii) Official visits abroad by a Vice-Chairperson shall be governed by Government's orders applicable to Secretaries in the Government of India.
- (iv) A Vice-Chairperson shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as provided in the Central Government Health Scheme (CGHS) as applicable to a retired Government servant. At places where the CGHS scheme is not in operation, he/she shall be entitled to reimbursement facilities provided under the Central Services (Medical Attendance) Rules.

13. Leave:

A Vice-Chairperson would be entitled to 30 days of earned leave, for every year of service. The payment of leave salary during leave shall be governed by rule 40 of Central Civil Services (Leave) Rules, 1972. A person would be entitled to encashment of 50% of earned leave to his credit at any time.

14. Leave Sanctioning Authority for the Vice-Chairperson :

The Chairperson shall be the authority competent to sanction leave to the Vice-Chairperson.

15. GPF/CPF, Pension and Gratuity

A Vice-Chairperson would be governed by Contributory Provident Fund Rules and no option to subscribe under General Provident Fund Rules will be available. Additional pension and gratuity will not be admissible for service rendered in the Authority.

16. Eligibility for Re-employment

There shall be a bar on private employment of Vice-Chairperson for two years in respect of organisations that fall within the operational jurisdiction of the National Environment Appellate Authority, after demitting office of Vice-Chairperson.

17. Transport

A Chairperson is eligible for reimbursement between Rs. 3000 and Rs. 5000 per month as fixed by the Department of Personnel and Training, from time to time, for the use and maintenance of his/her personal car for transportation between residence and office. This would include the salary of a driver who would not be a Government servant.

18. Accommodation

A Vice-Chairperson is entitled for House Rent Allowance at the rate of 30% of the basic pay drawn, if he/she stays in Delhi. Outside Delhi, he/she shall be entitled to rented unfurnished accommodation with built up area measuring around 300 sq. meters in the National Capital Region with suitable open land area appurtenant as permissible under the regulation of the concerned municipal bodies.

19. Special Provisions for retired persons appointed as Vice-Chairperson of the Authority

Where any person, being a retired government servant or retired servant of any other institution or autonomous body and in receipt of a pension in respect of any previous service is appointed as a Vice-Chairperson, the salary admissible to him/her under these rules shall be reduced by the amount of that pension and if he/she had received in lieu of a portion of that pension the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension.

20. Saving :—Any matter, not expressly provided in these rules, shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be final.

[File No. Q.-14011/1/97-CPW]
VIJAI SHARMA, Jt. Secy.

i 081 91/98-2

